संजयसिंह रामराव चव्हाण

बनाम

दत्तात्रेय गुलाबराव फाल्के और अन्य

(आपराधिक अपील संख्या 97/2015)

16 जनवरी, 2015

[न्यायाधिपति कुरियन जोसेफ और न्यायाधिपति अभय मनोहर सप्रे]

आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 – धारा 397 से 401 पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार - का दायरा - भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आपराधिक मामले का पंजीकरण - धारा 173(2) सीआर.पी.सी के तहत पुलिस द्वारा क्लोजर रिपोर्ट- मजिस्ट्रेट द्वारा स्वीकार किया गया - उच्च न्यायालय ने पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए मजिस्ट्रेट के आदेश को रद्द कर दिया और जांच अधिकारी को अभियोजन की मंजूरी के लिए अनुरोध करने का निर्देश दिया - अपील पर, आयोजित किया गया:

पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए न्यायालय को तब तक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, जब तक कि जिस निर्णय को संशोधित करने की मांग की गई है वह विकृत, कानून में अस्थिर, घोर गलत, स्पष्ट रूप से अनुचित, बिना किसी सामग्री पर आधारित, या भौतिक तथ्यों की उपेक्षा या जहां न्यायिक विवेक का प्रयोग मनमाने ढंग से किया जाता है। और मनमाने ढंग से - वर्तमान मामले में, क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार करने में मजिस्ट्रेट का आदेश तर्कसंगत था और विकृत नहीं था - मजिस्ट्रेट के आदेश को रद्द करने में उच्च न्यायालय उचित नहीं था - चूंकि आरोपी पर मुकदमा चलाने के लिए कोई मामला नहीं बनता है, अभियोजन के लिए मंजूरी की भी आवश्यकता नहीं है - भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 – धारा 7, 12, 13(1)(डी) और 13(2)-

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया-

1.1. किसी मामले का संज्ञान लेने के चरण में यह देखा जाना चाहिए कि क्या आगे की कार्यवाही शुरू करने की दृष्टि से किसी अपराध का न्यायिक नोटिस लेने के लिए पर्याप्त आधार है। अदालत सीआरपीसी की धारा 173(2) के तहत पुलिस द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से बाध्य नहीं है। यदि रिपोर्ट यह है कि कोई मामला नहीं बनता है, तो मजिस्ट्रेट अभी भी स्वतंत्र है, बल्कि बाध्य है, यदि उसके अनुसार कोई मामला बनता है, तो रिपोर्ट को अस्वीकार करने और संज्ञान लेने के लिए। सीआरपीसी की धारा 173(8) के तहत आगे की जांच का आदेश देने का भी उसे अधिकार है। [पैरा 11 और 14) [146-ए; 148-बी-डी]

एस. के. सिन्हा, मुख्य प्रवर्तन अधिकारी बनाम वीडियोकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और अन्य 2008 (2) एससीआर 36 = 2008 (2) एससीसी 492, भूषण कुमार और अन्य बनाम राज्य (एन. सी. टी.दिल्ली) और अन्य 2012 (2) एससीआर 696 = 2012 (5) एससीसी 424; श्रीमती. नागावा बनाम वीरन्ना शिवलिंगप्पा किंजलगी और अन्य 1976 (0) पूरक एससीआर 123 = 1976 (3) एससीसी 736-आश्रित

1.2. जब तक कि मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश विकृत न हो या अदालत द्वारा लिया गया दृष्टिकोण पूरी तरह से अनुचित न हो या किसी भी प्रासंगिक सामग्री पर विचार न किया गया हो या रिकॉर्ड की स्पष्ट गलत व्याख्या न हो, पुनरीक्षण अदालत के लिए आदेश को रद्द करना उचित नहीं है, केवल क्योंकि एक और दृष्टिकोण संभव है। पुनरीक्षण अदालत का उद्देश्य अपीलीय अदालत के रूप में कार्य करना नहीं है। पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का संपूर्ण उद्देश्य अदालत में आपराधिक न्यायशास्त्र के सिद्धांतों के अनुसार न्याय करने की शक्ति को संरक्षित करना है।

सीआरपीसी की धारा 397 से 401 के तहत अदालत की पुनरीक्षण शक्ति को अपील के बराबर नहीं माना जाना चाहिए। जब तक कि अदालत का निष्कर्ष, जिसके

फैसले को संशोधित करने की मांग की गई है, कानून में विकृत या अस्थिर नहीं दिखाया जाता है या पूरी तरह से गलत या स्पष्ट रूप से अनुचित या जहां निर्णय किसी भी सामग्री पर आधारित नहीं है या जहां भौतिक तथ्यों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है या जहां न्यायिक विवेक का प्रयोग मनमाने ढंग से या मनमाने ढंग से किया जाता है, अदालतें अपने पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार के प्रयोग में निर्णय में हस्तक्षेप नहीं कर सकती हैं। [पैरा 14) [148-डी-एच]

1.3. दूसरे प्रतिवादी द्वारा दायर की गई पहली शिकायत में - वास्तविक शिकायतकर्ता, अपीलकर्ता द्वारा रिश्वत की मांग का कोई आरोप नहीं है। मांग का आरोप विशेष रूप से आरोपी नंबर 2 के खिलाफ है। अपीलकर्ता के खिलाफ यह आरोप बाद में लगाया गया है। आरोप के समर्थन का एकमात्र आधार वह बातचीत है जिसे वॉयस रिकॉर्डर द्वारा रिकॉर्ड किया गया बताया जा रहा है। फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला निदेशालय ने कहा है कि बातचीत सुनने योग्य स्थिति में नहीं है और इसलिए, इसे स्पेक्ट्रोग्राफिक विश्लेषण के लिए नहीं माना जाता है। चूंकि वॉयस रिकॉर्डर स्वयं विश्लेषण के अधीन नहीं है, इसलिए अनुवादित संस्करण पर भरोसा करने का कोई मतलब नहीं है। स्रोत के बिना, अनुवाद की कोई प्रामाणिकता नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के लिए स्रोत और प्रामाणिकता दो प्रमुख कारक हैं। [पैरा 16] [149-सी-एफ]

अनवर पी. वी. बनाम पी. के. बशीर और अन्य ने 2014 (10) स्केल 660 पर भरोसा किया।

1.4. अभियोजन एक निरर्थक प्रयास बन जाता है क्योंकि उपलब्ध सामग्री यह नहीं दिखाती है कि अपीलकर्ता के खिलाफ कोई अपराध बनता है। आपराधिक अदालत की प्रक्रिया को उत्पीड़न के हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। असंबद्ध और अयोग्य अभियोजन भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटी का उल्लंघन है। [पैरा 17] [150-बी, सी, डी]

पेप्सी फूड्स लिमिटेड और अन्य बनाम विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट और अन्य 1997 (5) पूरक एससीआर 12 = 1998(5) एससीसी 749; कर्नाटक राज्य बनाम एल मुनिस्वामी और अन्य 1977 (3) एससीआर 113 =1977 (2) एससीसी 699; बिहार राज्य बनाम पी.पी.शर्मा, आईएएस और अन्य 1991 (2) एससीआर 1 = 1992 (1) पूरक धारा 222 - पर निर्भर

2. एक बार जब अभियोजन पक्ष का मानना है कि किसी आरोपी पर मुकदमा चलाने के लिए कोई मामला नहीं बनता है, जब तक कि अदालत अन्यथा न पाए, अभियोजन के लिए मंजूरी के लिए अनुरोध करने का कोई मतलब नहीं है। यदि अभियोजन केवल कष्टप्रद है, तो अभियोजन की मंजूरी नहीं दी जानी चाहिए मंज़ूर किया गया। मंजूरी दी जानी है या नहीं, इस पर विचार करते समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा ध्यान में रखा जाने वाला यह मुख्य विचारों में से एक है। [पैरा 18] (150-एफ-जी; 151-ए)

मनसुखलाल विट्ठलदास चौहान बनाम गुजरात राज्य 1997 (3) पूरक एस. सी. आर. 705 =1997 (7) एस.सी. सी 622-पर निर्भर था।

मामला कानून संदर्भः

2008 (2) एससीआर 36	उस पर भरोसा करें	पैरा 11
2012 (2) एससीआर 696	उस पर भरोसा करें	पैरा 12
1976 (0) पूरक एससीआर 123	उस पर भरोसा करें	पैरा 13
2014 (10) स्केल 660	उस पर भरोसा करें	पैरा 16
1997 (5) पूरक एससीआर 12	उस पर भरोसा करें	पैरा 17
1977 (3) एससीआर 113	उस पर भरोसा करें	पैरा 17

1991 (2) एससीआर 1 उस पर भरोसा करें पैरा 17

1997 (3) पूरक एससीआर 705 उस पर भरोसा करें पैरा 18

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार : आपराधिक अपील 97/2015

2012 के आपराधिक पुनरीक्षण आवेदन संख्या 361 में बॉम्बे में न्यायिक उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 07.08.2013 से।

हरिन रावल, रवींद्र केशवराव अदसुरे, सिद्धेश्वर बिरादर - अपीलार्थी के लिए।

अरुण पेडनेकर, सुनील कुमार वर्मा, अनिरुद्ध पी. मयी,चारुदत्त महिंद्राकर, ए. सेल्विन राजा - उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया था

न्यायाधिपति कुरियन:

1. अनुमति दी गई।

2. अपीलकर्ता महाराष्ट्र राज्य के बंड गार्डन पुलिस स्टेशन के 2010 के सीआर नंबर 3446 में आरोपी नंबर 1 है। मामला भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (इसके बाद पीसी अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 7, 12, 13 (1) (डी) के साथ पठित धारा 13 (2) के तहत दर्ज किया गया है।

3. उत्पत्ति पहले प्रतिवादी द्वारा दी गई अनुलग्नक-पी 7-शिकायत दिनांक 22.11.2010 है। उनके अनुसार, उन्हें अपनी भूमि के गैर-कृषि उपयोग के लिए प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए रिश्वत के रूप में 75,000/- रुपये की राशि का भुगतान करना पड़ा। शिकायत से उद्धृत करने के लिए:

"5 अक्टूबर 2009 को दैनिक लोकमत और लोकसत्ता अखबारों में "भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड पुणे" का एक विज्ञापन छपा। विज्ञापन पेट्रोल पंप की डीलरशिप देने के लिए था। मैंने इसके लिए कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को विधिवत आवेदन किया था। अनुसार प्रक्रिया के अनुसार मेरा साक्षात्कार 30 मार्च 2010 को आयोजित किया गया था। मुझे इस काम के लिए चुना गया था। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड पुणे के नियमों और शर्तों के अनुसार पिंपलसुतिताई शिरूर जिला पुणे में अपनी भूमि का "गैर कृषि प्रमाण पत्र" जमा करना मेरे लिए बाध्यकारी था। उक्त प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए मैंने दिनांक 9/9/2010 को मवई अनुविभागीय अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट पुणे को आवेदन किया। आवेदन के बाद मैंने उनकी मांग के अनुसार आवश्यक सभी दस्तावेज पूरे किये।

इसके बाद आज दिनांक 22/11/2010 को सुबह 11/20 बजे मैं गैर कृषि प्रमाण पत्र के बारे में पूछताछ करने के लिए मवई अनुविभागीय अधिकारी और मजिस्ट्रेट पुणे के कार्यालय में गया जो मुझे तब तक नहीं मिला था। उसी समय मेरी मुलाकात क्लर्क श्री सुहास सोमा से हुई। उन्होंने मुझे क्लर्क श्री लैंडगे से मिलने के लिए कहा जब मैं व्यक्तिगत रूप से श्री लैंडगे से मिला तो उन्होंने मुझे श्री संजयसिंह चव्हाण उपविभागीय अधिकारी मवई से मिलने के लिए कहा। उसी के तहत मैं श्री संजयसिंह चव्हाण अनुविभागीय अधिकारी मवई से उनके कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से मिला। उस समय उन्होंने मुझसे कारण पूछा कि मुझे गैरकृषि भूमि प्रमाण पत्र की आवश्यकता क्यों है। मैंने उन्हें पेट्रोल पंप का कारण बताया और जमीन का क्षेत्रफल भी बताया. इसके बाद उन्होंने मुझे क्लर्क सुहास सोमा से मिलने के लिए कहा।

जब मैं उनके कार्यालय से बाहर गया, तो उन्होंने अपने क्लर्क सुहास सोमा को अपने केबिन में बुलाया। श्रीसोमा के केबिन से बाहर आने के बाद उन्होंने मुझसे पूछा, "आप किस हद तक भुगतान करने को तैयार हैं?" उस वक्त मैंने उनसे पूछा, "चालान की रकम कितनी होगी?" उस समय उन्होंने कहा कि "चालान राशि कम है, अभ्यास के रूप में 1,00,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि का भुगतान करना होगा। यदि आपका मामला घर के लिए होता तो मैं बॉस से कम राशि के लिए अनुरोध करता। लेकिन जैसा कि आप हैं व्यापार करने जा रहे हैं तो आपको 1,00,000/- रुपए देने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उस समय मैंने कार्यालय अधीक्षक श्री सोमा से अनुरोध किया कि "यह राशि बहुत बड़ी है, मुझे कुछ रियायत दी जाए" जिस पर मेरे बीच समझौता हो गया। और उसने रिश्वत के रूप में 75,000/- रुपये की मांग की।"

4. उपरोक्त शिकायत के आधार पर विजिलेंस ने जाल बिछाया. प्रथम सूचना रिपोर्ट घटनाओं का वर्णन इस प्रकार करती है:

"चूंकि शिकायतकर्ता श्री दत्तात्रय फाल्के द्वारा दायर की गई शिकायत एक अपराध है जो भ्रष्टाचार विरोधी अधिनियम के तहत आता है और चूंकि हम श्री फाल्के द्वारा दायर शिकायत के आधार पर ऐसे अपराध का संज्ञान लेने के लिए एक जाल की व्यवस्था करने का निर्णय लेने के लिए अधिकृत हैं।" श्री चव्हाण उपविभागीय अधिकारी और उपविभागीय मजिस्ट्रेट, उपविभागीय मावई, पुणे और श्री सोमा, कार्यालय अधीक्षक (शिरस्तेदार), उपविभागीय कार्यालय, मावई पुणे को शिकायतकर्ता श्री फाल्के से रिश्वत लेते समय और उस उद्देश्य के लिए

एक लिखित पत्र देकर गिरफ्तार किया गया। माननीय चिकित्सा अधीक्षक, क्षेत्रीय मानसिक अस्पताल, यरवदा, पुणे को उनके कार्यालय से, 1 डॉ. अमल रंगनाथ जाधव, उम्र 25 वर्ष, व्यावसायिक-सेवा चिकित्सा अधिकारी, क्षेत्रीय मानसिक अस्पताल, यरवदा पुणे -6, सी43 बी जे में रहने वाले की सेवाएं। मेडिकल कॉलेज हॉस्टल, कलेक्टर कार्यालय के पास, पुणे-48, 2 डॉ. शार्न संतलू बडसे, उम्र 55 वर्ष, व्यवसाय-सर्विस, चिकित्सा अधिकारी, क्षेत्रीय मानसिक अस्पताल, येरवडा, पुणे-6, सुंदरबन सदन, नंदनवन, लोहागांव पुणे48 में रहते हैं। पंच गवाह के रूप में है। शिकायतकर्ता और पंच गवाहों को एक-दूसरे से परिचित कराया गया। शिकायतकर्ता द्वारा दायर शिकायत को संक्षेप में पंचों को बताया गया था। तदनुसार, हमने शिकायतकर्ता द्वारा दायर शिकायत को पंच गवाहों को पढ़ने के लिए दिया और यह आश्वस्त होने के बाद कि यह सही है, उन्होंने इसके नीचे हस्ताक्षर किए। इसके बाद, उपविभागीय अधिकारी और उपविभागीय मजिस्ट्रेट, उपविभाग मवई, पुणे श्री संजयसिंह चव्हाण और कार्यालय अधीक्षक (शिरस्तेदार) द्वारा मांगी गई रिश्वत के संबंध में शिकायतकर्ता श्री फाल्के द्वारा दायर की गई शिकायत को सत्यापित करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

इसके बाद दिनांक 22/11/2010 को 16.30 बजे मैं स्वयं शिकायतकर्ता श्री फाल्के, उपरोक्त दो पंच, पुलिस निरीक्षक श्री बी.आर. पाटिल, एंटी करप्शन ब्यूरो के कार्यालय से पुलिस निरीक्षक श्री बेलसरे साधु वासवानी चौक से होते हुए पैदल आए और नए प्रशासन भवन पुणे -1 में गए, उस समय हमने अपनी हिरासत से वॉयस रिकॉर्डर शुरू किया और उसे और उसके माइक को शिकायतकर्ता की शर्ट के

नीचे दबा दिया और शुरू कर दिया। उसी का रिकॉर्डिंग बटन। इसके बाद हमारे निर्देशानुसार, सबसे पहले शिकायतकर्ता श्री फाल्के और पंच नंबर 1 श्री जाधव उपविभागीय अधिकारी और उपविभागीय मजिस्ट्रेट, उपविभाग मवई, पुणे के कार्यालय में गए, जो नए प्रशासनिक भवन में है। उनके ठीक पीछे मैं पंच क्रमांक 2 श्री बेडासे तथा पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी उपविभागीय अधिकारी एवं उपविभागीय दंडाधिकारी मवई, उपविभागीय पुणे के कार्यालय के चारों ओर अलग-अलग खड़े थे ताकि किसी को कोई संदेह न हो। उक्त स्थान से आधे घंटे बाद शिकायतकर्ता श्री फाल्के एवं पंच क्रमांक 1 श्री जाधव बाहर आये. इसके बाद हम सभी वहां से वापस एंटी करप्शन ब्यूरो के पुणे कार्यालय आ गये। उक्त कार्यालय में वापस आने के बाद, हमने शिकायतकर्ता श्री फाल्के पर रखी रिकॉर्डिंग मशीन को बाहर निकाला और रिकॉर्डिंग के बटन को बंद कर दिया और पंचों के साथ शिकायतकर्ता श्री फाल्के, लोक सेवक श्री चव्हाण और श्री सोमा के बीच हुई बातचीत को सुना और इसका खुलासा हुआ। कि लोक सेवक श्री चव्हाण और श्री सोमा ने शिकायतकर्ता श्री फाल्के से 75,000/- रुपये की रिश्वत की मांग की है, मेरी, पंचों और शिकायतकर्ता की सहमति से, 23/11/2010 को आगे की कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया। तदनुसार शिकायतकर्ता एवं उपरोक्त पंचों को दिनांक 23/11/2010 को प्रातः 10.00 बजे भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, पुणे के कार्यालय में उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया।

दिनांक 23/11/2010 को प्रातः 10:00 बजे उपरोक्त पंच, शिकायतकर्ता श्री फाल्के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के पुणे कार्यालय में उपस्थित हुए। इसके बाद शिकायतकर्ता श्री फाल्के के पास जो भी कीमती चीजें थीं,

उनकी सूची बनाई गई। शिकायतकर्ता एवं पंच गवाहों को एन्थ्रेसीन पाउडर एवं पराबैंगनी प्रकाश के बारे में जानकारी दी गई एवं इसका प्रदर्शन भी दिखाया गया। परिवादी द्वारा रिश्वत के रूप में देने के लिए प्रस्तुत किये गये 75,000/- रूपये के सभी नोटों पर एन्थ्रेसिन पाउडर लगाया गया तथा उक्त नोटों को मोड़कर परिवादी की पैंट की दाहिनी ओर की जेब में रख दिया गया। नोटों पर एन्थ्रेसिन पाउडर लगाने वाले एवं डेमोस्ट्रेशन दिखाने वाले श्री एस.के. सतपुते पुलिस/614 को ट्रैप की कार्यवाही से बाहर किया गया।ट्रैप की कार्यवाही के संबंध में पंच गवाहों, अनुपूरक एवं ट्रैप की टीम के अन्य अधिकारी/कर्मचारियों को विस्तृत निर्देश दिये गये। तदनुसार, हमारे कार्यालय में विस्तृत प्री-ट्रैप पंचनामा तैयार किया गया। 23/11/2010 को उपविभागीय अधिकारी एवं उपविभागीय मजिस्ट्रेट मवई, पुणे, उपविभाग 1 के कार्यालय में नए प्रशासन भवन में दोपहर लगभग 12.02 बजे पंच नंबर 1 श्री जाधव की उपस्थिति में जाल की व्यवस्था की गई थी। लोक सेवक श्री सुहास रमेश सोमा, उम्र 46 वर्ष, कार्यालय अधीक्षक (शिरस्तेदार), उपविभागीय कार्यालय मवई, उपविभाग पुणे ने शिकायतकर्ता श्री फाल्के से रिश्वत की राशि की मांग की और व्यक्तिगत रूप से दराज नंबर 2 खोला जो दाईं ओर है उनकी मेज के किनारे हाथ रखकर शिकायतकर्ता श्री फाल्के से राशि उसमें रखने के लिए कहा। तदनुसार, जैसे ही शिकायतकर्ता श्री फाल्का ने उक्त राशि उक्त दराज में रखी, लोक सेवक श्री सोमा को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। जब रिश्वत की रकम के सम्पर्क में आये दस्तावेजों/कागजातों को पराबैंगनी प्रकाश के लैम्प में जांचा गया तो उस पर एन्थ्रेसिन पाउडर की हल्की नीली चमक दिखाई दी। रिश्वत की रकम के नोटों

की संख्या का प्री-ट्रैप पंचनामा में अंकित नोटों की संख्या से मिलान किया गया। यह देखा गया कि वे प्री-ट्रैप पंचनामा में उल्लिखित सभी नोटों के नंबरों के साथ बिल्कुल सटीक हैं। चूंकि रिश्वत की उक्त राशि वही राशि है जो लोक सेवक श्री सोमा ने शिकायतकर्ता श्री फाल्के से प्राप्त की थी और एंथ्रेसिन पाउडर की चमक थी इस पर देखा तो पंचों की मौजूदगी में उसे जब्त कर सील कर दिया गया। शिकायतकर्ता श्री फाल्के, लोक सेवक श्री चव्हाण और सोमा के बीच रिश्वत की राशि की मांग के संबंध में सभी बातचीत रिकॉर्ड की गई और इसे पंचों की उपस्थिति में सुना गया और इसकी स्क्रिप्ट तैयार की गई और इसका उल्लेख पंचनामा में किया गया है। इसी प्रकार, जब पंच क्रमांक 1 श्री जाधव से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि लोक सेवक श्री सोमा ने व्यक्तिगत रूप से कहा कि उन्हें रिश्वत की उक्त राशि श्री संजयसिंह रामराव चव्हाण, उम्र 44 वर्ष, उपविभागीय अधिकारी और उपविभागीय अधिकारी के निर्देशानुसार प्राप्त हुई है। मजिस्ट्रेट मावई सब डिवीजन पुणे. जाल के समय हुई सभी घटनाओं का एक विस्तृत पंचनामा पंचों की उपस्थिति में तैयार किया गया और उसकी प्रति लोक सेवक श्री संजयसिंह चव्हाण और सुहास सोमा को दी गई और उनके हस्ताक्षर लिए गए।"

5. जांच अधिकारी ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 173(2) के तहत अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की (इसके बाद इसे "सीआरपीसी के रूप में संदर्भित किया गया है) हालांकि गलती से 169 सीआरपीसी के रूप में उल्लेख किया गया है। क्लोजर रिपोर्ट से उद्धृत करने के लिए:

उक्त अपराध की समग्र जांच से एवं प्राप्त दस्तावेजों एवं साक्ष्यों से धारा 7, 12, 13(1)(डी) आर/डब्ल्यू के तहत मामला दर्ज करने हेतु। महाराष्ट्र सरकार, सामान्य प्रशासन के गोपनीय परिपत्र संख्या सीडीआर/1099/प्रा क्रा62/99/11-ए दिनांक 03/04/2000 के प्रावधानों के अनुसार भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) के तहत आरोपी लोक सेवक के खिलाफ कार्रवाई की गई। (1) श्री संजयसिंह रामराव चव्हाण, उपविभागीय अधिकारी और उपविभागीय मजिस्ट्रेट, मवई उपविभाग, जिला पुणे (2) श्री सुहास रमेश सोमा, अवाई कारकून (शिरस्तेदार) उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, मवई उपविभाग, पुणे, जब रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी तत्कालीन जांच अधिकारी श्री पी.बी. द्वारा धनवत, सहायक पुलिस आयुक्त, उप पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पुणे ने जावक संख्या पीबीजी/एसीपी/डीएसपी/एसीबी/पुणे/ 2011-283 दिनांक 21/02/2011 के माध्यम से महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, महाराष्ट्र को भेजा। राज्य, मुंबई ने पुलिस उपायुक्त/पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पुणे के माध्यम से धारा 19 के तहत अपेक्षित पूर्व-अभियोजन अनुमोदन/मंजूरी प्राप्त करने के लिए एपीएस के सक्षम अधिकारी महाराष्ट्र सरकार (राजस्व और वन) मंत्रालय, मुंबई को लिखने के लिए कहा। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988, और पुलिस उपाधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, पुणे ने अपने आउटवर्क्टी नंबर सीआर/438/पुणे/2010-1591 दिनांक 20/05/2011 के तहत ऐसी रिपोर्ट भेजी है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक एम.एस. मुंबई, अपराध के जांच दस्तावेजों की जांच के बाद, महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई ने अपने आदेश क्रमांक सीआर/438/पुणे/2010-4812 दिनांक 03/06/2011 द्वारा आदेश जारी किया है कि "चूंकि उक्त ट्रैप मामले में एपीएस श्री संजयसिंह रामराव चव्हाण, उपविभागीय अधिकारी और मजिस्ट्रेट, मवई, जिला पुणे के खिलाफ आरोप पत्र दायर करने के संबंध में कोई सबूत उपलब्ध नहीं है, उनके खिलाफ आरोप पत्र दायर न करने और उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया है। सक्षम अधिकारी

को विभागीय जांच का प्रस्ताव तैयार करने और भेजने के लिए और चूंकि एपीएस श्री सुहास रमेश सोमा अवाई कारकून (शिरास्तेदार), उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, मवई, जिला पुणे के खिलाफ सबूत उपलब्ध हैं, इसलिए अभियोजन पूर्व मंजूरी प्रस्ताव प्रस्तुत करने के आदेश जारी किए जाते हैं। उनके खिलाफ सक्षम न्यायालय में अभियोजन दायर करने के लिए उनके सक्षम अधिकारी। उक्त आदेश पुलिस उपायुक्त/पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, पुणे के क्रमांक सीआर/438/पुणे/2010-1846 दिनांक 09/06/2011 के माध्यम से प्राप्त हुए हैं। एवं उपर्युक्त आदेश की प्रतिलिपि अवलोकनार्थ प्रस्तुत की जा रही है।

इसलिए, यदि स्वीकृत हो, तो आरोपी लोक सेवक श्री संजयसिंह रामराव चव्हाण, उप-विभागीय अधिकारी और मजिस्ट्रेट, मवई उप-विभाग, पुणे, (वर्ग-1) को आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 169 के अनुसार उक्त अपराध से बरी करने का अनुरोध किया जाता है।"

6. विद्वान मजिस्ट्रेट ने 15.01.2012 को वास्तविक शिकायतकर्ता को नोटिस देने के बाद क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार कर ली। आदेश से प्रासंगिक भाग उद्धृत करने के लिए:

> "7....रिकॉर्ड से पता चलता है कि शिकायतकर्ता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। यदि शिकायत पर गौर किया जाए, तो ऐसा प्रतीत होता है कि आरोपी नंबर 1 की भूमिका इस प्रकार है कि 22.11.2010 को जब शिकायतकर्ता आरोपी नंबर 1 से मिला तो उसने उस उद्देश्य के बारे में पूछताछ की जिसके लिए एन.ए. प्रमाण पत्र की आवश्यकता थी और उसने शिकायतकर्ता को आरोपी नंबर 2 से मिलने के लिए कहा। शिकायत से पता चलता है कि पैसे की मांग और स्वीकृति आरोपी नंबर 2 द्वारा की गई थी। आरोपी नंबर 1 ने झूठे आरोप के लिए अपने प्रतिनिधित्व के साथ-साथ अन्य प्रासंगिक कागजात भी दाखिल

किए हैं।उन्होंने शिकायतकर्ता की पत्नी द्वारा दायर एन.ए. प्रमाण पत्र के लिए आवेदन, फिर शिकायतकर्ता और आरोपी नंबर 1 के कार्यालय के बीच सभी पत्राचार को रिकॉर्ड में रखा है ताकि यह दिखाया जा सके कि शिकायतकर्ता की पत्नी का आवेदन प्रक्रियाधीन था। इसके अलावा, आरोपी नंबर 1 ने अपने छुट्टी आवेदन की प्रति भी दाखिल की है जिसमें दिखाया गया है कि वह 15-11-2010 से 20.11.2010 तक छह दिनों के लिए चिकित्सा अवकाश पर था और उसके बाद 21.11.2010 को रविवार जोड़ने की अनुमति दी गई थी। आवेदक ने यह दिखाने के लिए टिकट दाखिल किया है कि उसने इस अवधि के दौरान यात्रा की है। आवेदक ने 24.11.2010 को दैनिक लोकमत में प्रकाशित एक समाचार को भी रिकॉर्ड में रखा है जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि जब 75,000/- रुपये की राशि स्वीकार की गई, तो आरोपी नंबर 1 अपने कार्यालय में नहीं था और यह आरोपी नंबर 2 सुहास सोमा ने स्वीकार कर लिया था।

8. यह माना जाना चाहिए कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने कागजात दाखिल किए हैं और कारण बताए हैं कि आरोपी नंबर 1 के खिलाफ कार्रवाई न करने का निर्णय क्यों लिया गया। यदि इन कागजातों का अवलोकन किया जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि पुलिस महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने संबंधित कागजातों पर विचार किया है और सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद एक तर्कसंगत आदेश पारित किया है। यह भी उल्लेख किया गया है कि तथाकथित सत्यापन के समय शिकायतकर्ता और आरोपी नंबर 1 के बीच दर्ज की गई अस्पष्ट बातचीत अभियोजन पक्ष की मदद नहीं करेगी और आरोपी नंबर 1 के खिलाफ मांग और स्वीकृति का कोई सबूत नहीं है, यह

नहीं कहा जा सकता है कि एंटी महानिदेशक -भ्रष्टाचार ब्यूरो ने उनसे पहले दस्तावेजों पर ध्यान नहीं दिया। जब आदेश कारण बताते हुए पारित किया गया था और चूंकि यह एक बोलने वाला आदेश है, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि सीआरपीसी की धारा 169 के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए पुलिस महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा दिया गया निर्देश कानूनन खराब है।

12. मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि वसंती दुबे बनाम मध्य प्रदेश राज्य के फैसले के मद्देनजर, न्यायालय क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर सकता है और धारा 190 आरडब्ल्यू के तहत आगे बढ़ सकता है। सीआरपीसी की धारा 156 या यह शिकायत पर संज्ञान ले सकता है और सीआरपीसी की धारा 202 के तहत सीधे जांच कर सकता है। हालांकि, मामले के कागजात देखने के बाद, यह पाया गया कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के तहत प्राधिकारी सही निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि कोई पर्याप्त आधार नहीं है। आरोपी नंबर 1 के खिलाफ कार्यवाही करने के परिणामस्वरूप, मैं सीआरपीसी की धारा 169 के तहत रिपोर्ट स्वीकार करता हूं।

आरोपी नंबर 1 के खिलाफ कार्यवाही बंद कर दी गई है और आरोपी नंबर 1 को आरोपमुक्त कर दिया गया है।"

7. असंतुष्ट, पहले प्रतिवादी - वास्तविक शिकायतकर्ता ने पुनरीक्षण में उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसके परिणामस्वरूप विवादित निर्णय आया। उच्च न्यायालय ने विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया और पुलिस महानिदेशक को अभियोजन की मंजूरी के अनुरोध को सक्षम प्राधिकारी को अग्रेषित

करने का निर्देश दिया। ट्रायल कोर्ट को भी मामले में कानूनी रास्ता अपनाने का निर्देश दिया गया। आक्षेपित निर्णय के पैराग्राफ-10 से 15 को उद्धृत करने के लिए:

> "4. मामले की जड़ यह है कि 22.11.2010 को शिकायतकर्ता/आवेदक और आरोपी नंबर 1 के बीच की बातचीत आवेदक द्वारा रिकॉर्ड की गई थी जैसा कि जांच एजेंसी द्वारा निर्देशित किया गया था, जो स्पष्ट रूप से प्रथम दृष्टया आरोपी प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा मांग का खुलासा करता है।
>
> Xxxx xxxx xxxx
>
> 10. कानूनी सलाहकार को संभवतः कानूनी ज्ञान है और वह शिकायतकर्ता के पूरक बयान पर प्रतिकूल टिप्पणी नहीं कर सकता ट्रैप के दौरान दर्ज किया गया, क्योंकि पूरक बयान पर पंच गवाह द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं। वह प्रथम दृष्टया अपने कानूनी ज्ञान को उचित दायरे में दर्शा सकता था, जिसकी कमी है। रिपोर्ट के अंत में यह लिखने का उनका कोई काम नहीं है कि आरोपी नंबर 2 के खिलाफ मामला कमजोर है क्योंकि इस रिपोर्ट को अभियोजन पक्ष में संबंधित लोगों द्वारा बचाव के रूप में इस्तेमाल और उठाया जा सकता है। इस तरह के अवांछित प्रयास अभियोजन को निराश और खंडित कर देंगे।
>
> 11. श्री हेमन्त वी.भट का हलफनामा हालांकि आरोपी प्रतिवादी का समर्थन करता है, तथापि, उन्हें भी समान रूप से कागजात का अध्ययन करना चाहिए था, उनके पास सीएफएसएल के संदिग्ध निष्कर्षों को स्वीकार करने का कोई कारण नहीं था।

शिकायतकर्ता और आरोपी-प्रतिवादी नंबर 1 के बीच रिकॉर्ड की गई बातचीत के संबंध में। उन्होंने मैनुअल का हवाला दिया है. मैनुअल का विरोध नहीं किया जाना चाहिए, हालांकि, इसे आरोपी-प्रतिवादी नंबर 1 के लाभ के लिए तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया है

12. विद्वान विशेष न्यायाधीश ने मूल रूप से रिपोर्ट या अधिवक्ता की राय का अध्ययन किया जिसकी अपेक्षा नहीं की गई थी। बचाव स्वीकार करके वह खुद ही बहक गया था। उन्हें मामले की तह तक जाना चाहिए था, अपना दिमाग लगाना चाहिए था. कानूनी विचार में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, उन्होंने एक शक्तिशाली अधिकारी द्वारा सत्ता के रंगीन प्रयोग का बेशर्म प्रयास देखा होगा, लेकिन विद्वान विशेष न्यायाधीश ट्रैक से चूक गए।

13. "वासंती दुबे बनाम मध्य प्रदेश राज्य ((2012)2 एससीसी 731)" के फैसले का संदर्भ निश्चित रूप से गलत था। उक्त मामले में मामले से निपटने वाले न्यायाधीश पुलिस द्वारा दी गई लगातार नकारात्मक रिपोर्ट से निराश थे। हालांकि, सामग्री की सराहना करने पर, सुप्रीम कोर्ट ने दर्ज किया, पहले से ही एक विशेष राज्य के लोकायुक्त के निष्कर्ष थे कि उक्त आरोपी के खिलाफ कोई सामग्री नहीं है। विद्वान न्यायाधीश को इस पहलू की अनदेखी नहीं करनी चाहिए थी।

14. माननीय उच्चतम न्यायालय ने "सीबीआई के माध्यम से महाराष्ट्र राज्य बनाम महेश जी.जैन" मामले में आपराधिक अपील संख्या 28 मई 2013 को निर्णय 2009 के 2345 में मंजूरी से संबंधित मापदंडों के बारे में भी बताया गया है।

15. परिणामस्वरूप, सीआरपीसी की धारा 169 के तहत रिपोर्ट स्वीकार करने वाले विद्वान विशेष न्यायाधीश के आदेश को रद्द कर दिया जाता है। सीआरपीसी की धारा 169 के तहत रिपोर्ट खारिज की जाती है। विद्वान विशेष न्यायाधीश या अन्वेषक को मामले में कानूनी पाठ्यक्रम का पालन करना होगा। कानून के अनुसार आदेश पारित करने के लिए उपयुक्त मंजूरी प्राधिकारी को मामले के कागजात अग्रेषित करने के लिए डीजीपी को सिखाया गया। अवलोकन प्रथम दृष्टया प्रकृति के हैं।"

8. पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील का कहना है कि अपीलकर्ता ने 1995 से बेदाग सेवा की है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है ताकि उसकी छवि खराब हो और उसका करियर खराब हो जाए। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में कानूनी सलाहकार पीसी अधिनियम के तहत अपराधों की सुनवाई के लिए विशेष अदालत के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे और उनकी कानूनी सलाह पर ही महानिदेशक, पुलिस इस निष्कर्ष पर पहुंची कि अपीलकर्ता के खिलाफ कार्यवाही करने का कोई आधार नहीं है। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि सक्षम क्षेत्राधिकार के मजिस्ट्रेट ने पूरे रिकॉर्ड को देखने के बाद और अपीलकर्ता के खिलाफ आगे नहीं बढ़ने का एक सूचित निर्णय लिया है, उच्च न्यायालय द्वारा उक्त आदेश को केवल इसलिए रद्द करना उचित नहीं है क्योंकि एक अन्य दृष्टिकोण भी संभव है। दूसरी ओर, उत्तरदाताओं के विद्वान वकील का कहना है कि पुनरीक्षण में उच्च न्यायालय द्वारा मामले की खूबियों को देखना और निर्देश देना पूरी तरह से उचित था।अपीलार्थी के विरुद्ध कार्यवाही करें। अंततः दोष सिद्ध करने के लिए साक्ष्य है या नहीं, यह संज्ञान लेने के समय देखने की आवश्यकता नहीं है; आवश्यकता केवल यह देखने की है कि मामले में आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार है या नहीं।

9. शुरुआत में, हम यह स्पष्ट कर देते हैं कि जहां भी जांच अधिकारी या अदालतों द्वारा 169 सीआरपीसी का संदर्भ दिया जाता है, उसे धारा 173 सीआरपीसी के संदर्भ के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। धारा 169 सीआरपीसी सबूत होने पर आरोपी की रिहाई का प्रावधान करती है। कमी है, जबकि जांच पूरी होने पर रिपोर्ट सीआरपीसी की धारा 173 के तहत है, आसान संदर्भ के लिए, हम प्रासंगिक प्रावधान उद्धृत कर सकते हैं:

> "169. साक्ष्य में कमी होने पर अभियुक्त की रिहाई यदि, इस अध्याय के तहत जांच करने पर, पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के पास भेजने को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त सबूत या संदेह का उचित आधार नहीं है ऐसा अधिकारी, यदि ऐसा व्यक्ति हिरासत में है, तो उसे बांड निष्पादित करने पर, जमानतदारों के साथ या उसके बिना, जैसा कि ऐसा अधिकारी निर्देश दे सकता है, रिहा कर देगा, यदि आवश्यक हो तो अपराध का संज्ञान लेने के लिए सशक्त मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होने के लिए। पुलिस रिपोर्ट करेगी और अभियुक्त पर मुक़दमा चलायेगी या उसे मुक़दमे के लिए प्रतिबद्ध करेगी।"
>
> जांच अधिकारी द्वारा 05.07.2011 को जो प्रस्तुत किया गया है वह वास्तव में सीआरपीसी की धारा 173 के तहत जांच पूरी होने पर एक रिपोर्ट है।"

10. विचार के लिए दो प्रश्न उठते हैं:

1. एक बार जब सक्षम क्षेत्राधिकार का मजिस्ट्रेट, उचित विवेक के आधार पर, सीआरपीसी की धारा 173(2) के तहत पुलिस द्वारा प्रस्तुत क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार

करने का निर्णय लेता है, तो क्या उच्च न्यायालय द्वारा अपने पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार के प्रयोग में इसे रद्द करना उचित है? क्योंकि दूसरा दृश्य संभव हो सकता है?

2. क्या जांच अधिकारी को सक्षम प्राधिकारी से अभियोजन की मंजूरी के लिए अनुरोध करने का निर्देश देना उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में है?

11. किसी मामले का संज्ञान लेने के चरण में यह देखा जाना चाहिए कि क्या आगे की कार्यवाही शुरू करने की दृष्टि से किसी अपराध का न्यायिक नोटिस लेने के लिए पर्याप्त आधार है। एस.के. सिन्हा मुख्य प्रवर्तन अधिकारी बनाम वीडियोकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और अन्य१ मामले में इस न्यायालय ने प्रक्रिया का विश्लेषण किया है और इसे इस प्रकार माना गया है:

> "19. अभिव्यक्ति "संज्ञान" को संहिता में परिभाषित नहीं किया गया है। लेकिन शब्द (संज्ञान) अनिश्चितकालीन महत्व का है। इसका आपराधिक कानून में कोई गूढ या रहस्यमय महत्व नहीं है। इसका केवल अर्थ है "जागरूक होना' और जब इसका उपयोग किया जाता है किसी न्यायालय या न्यायाधीश के संदर्भ में, इसका अर्थ "न्यायिक रूप से नोटिस लेना" है। यह उस बिंदु को इंगित करता है जब कोई अदालत या मजिस्ट्रेट किसी अपराध के संबंध में कार्यवाही शुरू करने के उद्देश्य से किसी अपराध का न्यायिक नोटिस लेता है, जिसे किसी के द्वारा किया गया कहा जाता है।
>
> 20. "संज्ञान लेना" में किसी भी प्रकार की कोई औपचारिक कार्रवाई शामिल नहीं है। यह तब घटित होता है जब मजिस्ट्रेट किसी अपराध के संदिग्ध होने पर अपना दिमाग लगाता है। आपराधिक कार्यवाही शुरू होने से पहले संज्ञान लिया जाता है। इस प्रकार संज्ञान लेना एक वैध परीक्षण आयोजित करने के लिए एक अनिवार्य शर्त या पूर्व शर्त

है। संज्ञान किसी अपराध का लिया जाता है, अपराधी का नहीं। मजिस्ट्रेट ने किसी अपराध का संज्ञान लिया है या नहीं, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है और सार्वभौमिक अनुप्रयोग का कोई नियम निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि मजिस्ट्रेट ने कब संज्ञान लिया है।"

12. भूषण कुमार और अन्य बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली) और अन्य२ मामले में उपरोक्त दृष्टिकोण का समर्थन किया गया है:

"11. मुख्य प्रवर्तन अधिकारी बनाम वीडियोकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (एससीसी पृष्ठ 499, पैरा 19) में इस न्यायालय द्वारा अभिव्यक्ति"संज्ञान" को इस प्रकार समझाया गया था कि "इसका मतलब केवल 'जागरूक होना और जब संदर्भ के साथ उपयोग किया जाता है' किसी न्यायालय या न्यायाधीश के लिए इसका तात्पर्य 'न्यायिक रूप से नोटिस लेना' है। यह उस बिंदु को इंगित करता है जब कोई अदालत या मजिस्ट्रेट किसी अपराध के संबंध में कार्यवाही शुरू करने की दृष्टि से किसी अपराध का न्यायिक नोटिस लेता है, जैसा कि कहा जाता है कि यह किसी के द्वारा किया गया है। यह कार्यवाही शुरू करने से बिल्कुल अलग बात है; बल्कि यह मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश द्वारा कार्यवाही शुरू करने से पहले की शर्त है। संज्ञान मामलों का लिया जाता है, व्यक्तियों का नहीं। संहिता की धारा 190 के तहत, शिकायत में दिए गए कथनों पर न्यायिक दिमाग का प्रयोग ही संज्ञान बनता है। इस स्तर पर, मजिस्ट्रेट को संतुष्ट होना होगा कि आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार है या नहीं और सजा के लिए पर्याप्त आधार है या नहीं। दोषसिद्धि का समर्थन करने के लिए साक्ष्य पर्याप्त

है या नहीं यह केवल मुकदमे में ही निर्धारित किया जा सकता है, पूछताछ के चरण में नहीं। यदि आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार है तो मजिस्ट्रेट को संहिता की धारा 204 के तहत प्रक्रिया जारी करने का अधिकार है।"

13. श्रीमती नागव्वा बनाम वीरन्ना शिवलिंगप्पा किंजल्गी और अन्य३ में, मजिस्ट्रेट संज्ञान लेने के चरण में किस हद तक जा सकता है, इस पर चर्चा की गई है। उद्धरण के लिए:

"5.... यह सच है कि इस निर्णय पर पहुंचने में कि क्या कोई प्रक्रिया जारी की जानी चाहिए, मजिस्ट्रेट शिकायत के चेहरे पर या शिकायतकर्ता द्वारा इसके समर्थन में दिए गए सबूतों में दिखाई देने वाली अंतर्निहित असंभाव्यताओं पर विचार कर सकता है आरोप लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि अभियुक्त की दोषसिद्धि की संभावना और उसके खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला स्थापित होने की संभावना के बीच सीमा की एक बहुत पतली रेखा है। मजिस्ट्रेट को इस मामले में निस्संदेह विवेकाधिकार दिया गया है और विवेक का प्रयोग उसे न्यायिक रूप से करना होगा एक बार जब मजिस्ट्रेट अपने विवेक का प्रयोग कर लेता है तो यह उच्च न्यायालय या यहां तक कि इस न्यायालय के लिए भी नहीं है कि वह मजिस्ट्रेट के विवेक के स्थान पर अपने विवेक का प्रयोग करे या शिकायत में आरोपों का पता लगाने के लिए गुण-दोष के आधार पर मामले की जांच करे। यदि साबित हो जाता है, तो अंततः आरोपी को दोषी ठहराया जाएगा"

14. संज्ञान एक ऐसी प्रक्रिया है जहां अदालत किसी अपराध का न्यायिक नोटिस लेती है ताकि कानून के कथित उल्लंघन के संबंध में कार्यवाही शुरू की जा सके। पुलिस

द्वारा अपराध की जांच की जाती है। इसमें कोई संदेह नहीं है, अदालत सीआरपीसी की धारा 173(2) के तहत पुलिस द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से बाध्य नहीं है। यदि रिपोर्ट यह है कि कोई मामला नहीं बनता है, तो मजिस्ट्रेट अभी भी स्वतंत्र है, बल्कि बाध्य है, यदि उसके अनुसार मामला बनता है। उस रिपोर्ट को अस्वीकार करने और संज्ञान लेने के लिए बनाया गया है। उसके लिए आगे ऑर्डर करना भी खुला है सीआरपीसी की धारा 173(8) के तहत जांच हमारे सामने आए मामले में विद्वानमजिस्ट्रेट ने पुलिस द्वारा दायर रिपोर्ट तक सीमित न रहकर मामले के पूरे रिकॉर्ड का अध्ययन किया और एक तर्कसंगत आदेश पारित किया कि यहउपयुक्त मामला नहीं है। अपीलकर्ता को प्रक्रिया जारी करने के उद्देश्य से संज्ञान लेंजब तक कि मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश विकृत न हो या अदालत द्वारा लिया गया दृष्टिकोण पूरी तरह से अनुचित न हो या किसी भी प्रासंगिक सामग्री पर विचार न किया गया हो या रिकॉर्ड की स्पष्ट गलत व्याख्या न हो, पुनरीक्षण अदालत के लिए आदेश को रद्द करना उचित नहीं है, केवल इसलिए दूसरा दृश्य संभव है. पुनरीक्षण न्यायालय का उद्देश्य अपीलीय न्यायालय के रूप में कार्य करना नहीं है। पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का पूरा उद्देश्य आपराधिक न्यायशास्त्र के सिद्धांतों के अनुरूप न्याय करने की अदालत में शक्ति को संरक्षित करना है। सीआरपीसी की धारा 397 से 401 के तहत अदालत की पुनरीक्षण शक्ति को अपील के बराबर नहीं माना जाना चाहिए। जब तक कि अदालत का निष्कर्ष जिसके निर्णय को संशोधित करने की मांग की गई है, कानून में विकृत या अक्षम्य नहीं दिखाया गया है या पूरी तरह से गलत या स्पष्ट रूप से अनुचित है या जहां निर्णय किसी भी सामग्री पर आधारित नहीं है या जहां भौतिक तथ्यों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है या जहां न्यायिक विवेकाधिकार नहीं है मनमाने ढंग से या मनमर्जी से प्रयोग किया जाता है, तो अदालतें अपने पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार के प्रयोग में निर्णय में हस्तक्षेप नहीं कर सकती हैं।

15. धारा 190(1)(बी) सीआरपीसी के तहत किसी अपराध का संज्ञान लेने का पूरा उद्देश्य मामले में शामिल आरोपियों को धारा 204 सीआरपीसी के तहत प्रक्रिया जारी करके सीआरपीसी के अध्याय XVI के तहत कार्यवाही शुरू करना है, इसमें कोई संदेह नहीं है मासूमियत लेकिन भागीदारी जो इस स्तर पर महत्वपूर्ण है। एक बार जब किसी आरोपी के लिए कथित अपराध का गठन करने के लिए कानूनी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो जातीं, तो उसके खिलाफ संज्ञान लेने और आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं है।

16. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि दूसरे प्रतिवादी (वास्तविक शिकायतकर्ता) द्वारा दायर की गई पहली शिकायत में, अपीलकर्ता द्वारा रिश्वत की मांग का कोई आरोप नहीं है। मांग का आरोप विशेष रूप से केवल आरोपी नंबर 2 के खिलाफ है, अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप केवल बाद में लगाया गया है। जो भी हो, आरोप के समर्थन का एकमात्र आधार वह बातचीत है जिसे वॉयस रिकॉर्डर द्वारा रिकॉर्ड किया गया बताया जा रहा है। फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला निदेशालय, महाराष्ट्र राज्य ने अनुलग्नक-बी रिपोर्ट के माध्यम से कहा है कि बातचीत सुनने योग्य स्थिति में नहीं है और इसलिए, इसे स्पेक्ट्रोग्राफिक विश्लेषण के लिए नहीं माना जाता है। उत्तरदाताओं के विद्वान वकील का कहना है कि बातचीत का अनुवाद किया गया है और उसे पंचगवाहों द्वारा सत्यापित किया गया है। माना कि पंच गवाहों ने बातचीत नहीं सुनी, क्योंकि वे कमरे में मौजूद नहीं थे। चूंकि वॉयस रिकॉर्डर स्वयं विश्लेषण के अधीन नहीं है, इसलिए अनुवादित संस्करण पर भरोसा करने का कोई मतलब नहीं है। स्रोत के बिना, अनुवाद की कोई प्रामाणिकता नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के लिए स्रोत और प्रामाणिकता दो प्रमुख कारक हैं, जैसा कि इस न्यायालय ने अनवर पी.वी. बनाम पी.के. बलशीर और अन्य४ में माना था।

17. मजिस्ट्रेट, रिकॉर्ड देखने और पक्षों को सुनने के बाद, इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अपीलकर्ता के खिलाफ पीसी अधिनियम के प्रावधानों के तहत कोई अपराध नहीं

बनता है, ताकि उस पर मुकदमा चलाया जा सके। यहां तक कि उच्च न्यायालय के अनुसार, "इस मामले का सार 22.11.2010 को शिकायतकर्ता और आरोपी नंबर 1 के बीच हुई बातचीत है"। वह वार्तालाप अश्रव्य है और उसे साक्ष्य के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। इसलिए, एक बार जब 'क्रक्स' चला जाता है, तो अधिरचना भी गिर जाती है, पैरों की कमी हो जाती है। इसलिए, अभियोजन एक निरर्थक प्रयास बन जाता है क्योंकि उपलब्ध सामग्री यह नहीं दिखाती है कि अपीलकर्ता के खिलाफ कोई अपराध बनता है। दुर्भाग्य से उच्च न्यायालय इस भाग से चूक गया। "आपराधिक मामले में किसी आरोपी को समन करना एक गंभीर मामला है। आपराधिक कानून को तत्काल लागू नहीं किया जा सकता..."(पेप्सी फूड्स लिमिटेड और अन्य बनाम विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट और अन्य५, पैराग्राफ-28)। आपराधिक अदालत की प्रक्रिया को उत्पीड़न के हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। "एक बार जब यह पाया जाता है कि किसी आरोपी को अपराध से जोड़ने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं है, तो उस पर मुकदमा चलाने का कोई मतलब नहीं है। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ ऐसी कार्यवाही जारी रखने की अनुमति देना जनता के समय और धन की सरासर बर्बादी होगी" (कर्नाटक राज्य बनाम एल. मुनिस्वामी और अन्य६ देखें। अपात्र और अयोग्य अभियोजन भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटी का उल्लंघन है। "...अनुच्छेद 21 प्रत्येक व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का आश्वासन देता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता शब्द का दायरा सबसे व्यापक है जो विभिन्न प्रकार के अधिकारों को कवर करता है जो एक नागरिक की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का गठन करता है। इसका हनन केवल इसमें निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार होगा संहिता और साक्ष्य अधिनियम संविधान के सर्वोच्च कानून के आदेश के अनुरूप है। ..."(बिहार राज्य बनाम पी.पी. शर्मा, आईएएस और अन्य७ पैराग्राफ -60)।

18. एक बार जब अभियोजन यह तय कर लेता है कि किसी आरोपी पर मुकदमा चलाने के लिए कोई मामला नहीं बनता है, जब तक कि अदालत अन्यथा न

पाए, अभियोजन की मंजूरी के लिए अनुरोध करने का कोई मतलब नहीं है। यदि अभियोजन केवल कष्टप्रद है, तो अभियोजन की मंजूरी नहीं दी जाएगी। मंजूरी दी जानी है या नहीं, इस पर विचार करते समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा ध्यान में रखा जाने वाला यह मुख्य विचारों में से एक है। मनसुखलाल विट्ठलदास चौहान बनाम गुजरात राज्य८ में, इस न्यायालय ने स्पष्ट शब्दों में यह स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी अदालत किसी प्राधिकारी को अभियोजन की मंजूरी देने के लिए सकारात्मक निर्देश जारी नहीं कर सकती है। उद्धरण के लिए:

> "32. सचिव को मंजूरी देने का निर्देश जारी करके, उच्च न्यायालय ने सचिव के लिए अन्य सभी विकल्प बंद कर दिए और उसे केवल एक दिशा में आगे बढ़ने और केवल एक ही तरीके से कार्य करने के लिए मजबूर किया, अर्थात् अपीलकर्ता के अभियोजन को मंजूरी देने के लिए सचिव को इस बात पर विचार करने की अनुमति नहीं दी गई कि क्या अपीलकर्ता पर मुकदमा चलाना संभव होगा, क्या अवैध अनुसमर्थन के हर्षद्रय की शिकायत, जिसे "जाल" द्वारा समर्थित करने की मांग की गई थी, झूठी थी और क्या अभियोजन विशेष रूप से कष्टप्रद होगा जैसा कि इसमें था सरकार को जानकारी थी कि फर्म को एक बार काली सूची में डाल दिया गया था और इस अनुबंध के संबंध में फर्म द्वारा सरकार को कुछ राशि का भुगतान करने की मांग की गई थी। इस प्रकार अभियोजन को मंजूरी न देने का विवेक उच्च न्यायालय द्वारा छीन लिया गया था।"

19. उच्च न्यायालय ने अपने विचारों को प्रतिस्थापित करने में अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया और वह भी बिना किसी कानूनी आधार के इसलिए विवादित आदेश को रद्द किया जाता है। अपील की अनुमति है.

कल्पना के त्रिपाठी अपील की अनुमति दी गई।

---

१ (2008) 2 एसइसी 492.

२ . (2012) 5 एसइसी 424.

३ . (1976) 3 एसइसी 736.

४ . 2014 (10) स्केल 660

५ (1998) 5 एसइसी 749.

६ (1977) 2 एसइसी 699.

७ 1992 पूरक (1) sec 222.

८ . (1997) 1 एसइसी 522

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता निशा पालीवाल द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।